धनबल और एक अन्य

बनाम

तमिलनाडु राज्य

13 दिसंबर, 1979

[एस.मुर्तजा फजल अली, पी.एस. कैलासम और ए.डी.कौशल, जेजे.]

सन्देह का लाभ - जब अभियुक्त के प्रकट कार्य को दिखाने के लिए कोई कानूनी साक्ष्य नहीं है तो संदेह के लाभ का अनिवार्य रूप से अनुसरण करना चाहिए।

साक्ष्य - समादेशिक न्यायालय में दिए गए साक्ष्य का सत्र न्यायालय के अभिलेख में स्थानांतरण, स्वीकार्यता - क्या साक्ष्य अधिनियमकी धारा १४५ के तहत आवश्यक के रूप में गवाहों का ध्यान एक-एक करके विपरीत बयान की ओर लाया जाना चाहिए -दंड प्रक्रिया संहिता, 1898, धारा 288।

मजिस्ट्रेटों द्वारा बयान दर्ज करना - केवल यह तथ्य कि पुलिस के पास यह संदेह करने के कारण थे कि गवाह को पकड़ लिया जा सकता है और उचित है कि उनके बयान मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किये जाएँ, इस प्रकार दर्ज किये गए गवाहों के बयान को दागदार नहीं बनाया जायेगा – धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता.

अपीलार्थी और तीसरा अभियुक्त मृतक रसायल के भाई थे। उन पर हत्या का अपराध करने का आरोप लगाया गया और उन्हें दोषी पाया गया और सत्र न्यायालय द्वारा धारा 302 आई.पी.सी. सपठित धारा 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपील में उच्च न्यायालय ने तीसरे अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया लेकिन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

विशेष अनुमति द्वारा अपील में, तीन तर्क उठाई गईं, अर्थात् (i) दोनों अपीलार्थियों को पूरी तरह से सत्र न्यायालय में चिह्नित पीडब्ल्यू 1, 2 और 5 के वापस

लिए गए साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जाना गलत था (ii) धारा 288 के तहत चिह्नित साक्ष्य अस्वीकार्य था क्योंकि इसे केवल गवाहों को पूरा पढ़ा गया था और साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 में आवश्यक के रूप में उन्हें पारित नहीं किया गया था और (iii) दूसरे अपीलार्थी का मामला तीसरे अभियुक्त के समान था और उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए था।

द्वितीय अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करते हुए और प्रथम की अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने -

अभिनिर्धारित किया : 1. तथ्यों और मामले की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि यह पहला अपीलार्थी था जिसने घातक चोट पहुंचाई और दूसरे अपीलार्थी से किसी उकसावे की आवश्यकता नहीं थी। तीसरे अभियुक्त के साथ दूसरे अपीलार्थी की उपस्थिति के अलावा किसी भी प्रकट कार्य के बारे में कोई सबूत नहीं था। यह सबसे अधिक संभावना नहीं थी कि दूसरे अपीलार्थी ने पहले अभियुक्त को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप पहले अभियुक्त ने घातक चोट कारित की। दूसरा अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। [495 ई-जी]

2. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया जाएगा यदि गवाहों के बयानों को उनके सामने विस्तार से पढ़ा जाता है और वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उन बयानों को समादेशिक न्यायालय में दिया है। इस मामले में आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है। [497 एफ-जी]

तारा सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1951] एस.सी.आर. 729, भगवान सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1952] एस.सी.आर. 812 राजस्थान राज्य बनाम कर्तार सिंह, [1971] 1 एस.सी.आर. 56; संदर्भित किया गया।

3. अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी कभी-कभी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गवाह का बयान दर्ज करना समीचीन समझता है। ऐसा तब होता है जब

अपराध के गवाह अभियुक्त के साथ निकटता से जुड़े होते हैं या जहाँ अभियुक्त बहुत प्रभावशाली होते हैं जिसके परिणामस्वरूप गवाहों पर प्रभाव डाला जा सकता है। दर्ज किए गए 164 बयान में मजिस्ट्रेट का समर्थन है कि बयान गवाह द्वारा दिया गया था। [499 ए-सी]

4. केवल यह तथ्य कि पुलिस के पास संदेह करने के कारण थे कि गवाह को प्रभावित किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट द्वारा उनके बयान दर्ज करना समीचीन था, इस प्रकार दर्ज किए गए गवाहों के बयानों को दूषित नहीं करेगा। यदि गवाह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान पर कायम रहता है, तो कोई समस्या पैदा नहीं होती है। यदि गवाह समादेशिक न्यायालय में धारा 164 के तहत अपने द्वारा दिए गए बयान से मुकर जाता है, तो गवाह से उसके पहले के बयान पर प्रति-परिक्षण किया जा सकता है। लेकिन यदि वह जांच से पहले धारा 164 के तहत दिए गए अपने बयान पर कायम रहता है और सत्र न्यायालय में उससे जवाब देता है, तो धारा 288, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करना है कि गवाह पर विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं। यह तथ्य कि पुलिस के पास मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज धारा 164 का बयान था, अपने आप में उसके साक्ष्य को दूषित नहीं करेगा। [499 सी-एफ]

रामचंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1968] 3 एससीआर 354; व्याख्या की गई और भरोसा किया।

5. साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 यह स्पष्ट करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान पर समादेशिक न्यायालय में गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की पुष्टि करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। यद्यपि दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयानों का सबूत नहीं है, लेकिन यह समादेशिक न्यायालय में पहले जो कहा गया है, उसकी पुष्टि करता है। [499 एफ-जी]

राजस्थान राज्य बनाम कर्तार सिंह, [1971] 1 एससीआर 56; अनुसरण किया गया।

6. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के तहत दर्ज एक गवाह का बयान धारा 288 के तहत दूसरे गवाह के बयान की पुष्टि कर सकता है। बयानों को कानून में ठोस साक्ष्य के रूप में माना जाता है और एक गवाह के बयान को दूसरे की पुष्टि करने वाला मानने में कोई दोष नहीं है। [500 ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 406/1976

मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील संख्या 823/74 में निर्णय और आदेश दिनांक 1-9-1975 से उत्पन्न विशेष अनुमति द्वारा अपील।

ए.एन.मुल्ला, ए.टी.एम. संपत और पी.एन.रामलिंगम, अपीलार्थी की ओर से।

ए.वी.रंगम, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

कैलासम, न्यायाधिपति.

यह अपील एस.सी. 26/1974 में अभियुक्त 1 और 2 द्वारा सत्र न्यायाधीश, दक्षिण आरकोट पीठ की फाइल पर विशेष अनुमति द्वारा, मद्रास उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 823/1974 में दिनांक 1 सितम्बर 1975 को उनकी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ है।

दो अपीलार्थियों और मुथुथामिजाहारसन सत्र न्यायालय में अभियुक्त संख्या 1-3 थे। पहले अपीलार्थी को आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरे अपीलार्थी और तीसरे अभियुक्त को धारा

302 आई.पी.सी. सपठित धारा 149 के तहत अपराध का दोषी पाया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दो अपीलार्थियों और तीसरे अभियुक्त की अपील पर, तीसरे अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था और अपीलार्थी संख्या 1 और 2 हमारे समक्ष हैं।

मृतक रसायल अपीलार्थियों और तीसरे अभियुक्त की बहन है। पहला अभियुक्त धनबल सबसे बड़ा और दूसरा अपीलार्थी और तीसरा अभियुक्त उसके छोटे भाई हैं। दूसरे अपीलार्थी ने रसायल की बेटी लक्ष्मी से शादी की। कीलाकराई गाँव में रसायल के पास लगभग 5 एकड़ भूमि थी। उसने एक आम मुख्तारनामा प्रदर्श पी.15 दिनांक 31 अगस्त 1970 को दुसरे अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया। रसायल, अपने पति को खोने के बाद, एक अनैतिक जीवन जीने लगी जिसे उसके भाई नापसंद करते थे। नतीजतन, रसायल ने दूसरे अपीलार्थी के पक्ष में मुख्तारनामा के बावजूद अपनी जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया। पक्षों के बीच गलतफहमी थी और रसायन ने पुलिस से शिकायत की कि उसके भाइयों ने उसे दूर करने की धमकी दी थी।

घटना की तारीख 5 दिसंबर, 1973 को दोपहर लगभग 1:30 बजे, जब रसायल और उसका खेत नौकर परमशिवम, पी.डब्ल्यू.4, उसके खेत में खरपतवार हटाने का काम कर रहे थे, तो दो अपीलार्थी और तीसरा अभियुक्त उस स्थान पर एकत्र हो गए जहाँ रसायल काम कर रही थी। पहला अपीलार्थी वीचारुवल से लैस था, दूसरा अपीलार्थी कुदाल से लैस था और तीसरा निहत्था था। उन्हें देखकर, रसायल अपने खेतों से सटे नहर की ओर दौड़ी। तीसरे अभियुक्त ने पहले अपीलार्थी को यह कहते हुए उसे काटने के लिए उकसाया कि वह अनैतिक जीवन जी रही है और उसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसके बाद, पहले अपीलार्थी ने रसायल को वीचारुवल से उसकी गर्दन के दाहिने हिस्से में काट दिया और वह शोर करते हुए चैनल में गिर गई। दूसरे अपीलार्थी ने कहा कि उसे उस पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए और उसका सिर उसके शरीर से काट दिया जाना

चाहिए, क्योंकि वह एक अनैतिक महिला है। इसके बाद, पहले अपीलार्थी ने उसके बालों को बाएं हाथ से पकड़ लिया और उसकी गर्दन को वीचारुवल से काट दिया, जिससे धड़ से सिर अलग हो गया। इस घटना को रामलिंगम पी.डब्ल्यू.1 और रामकृष्णन पी.डब्ल्यू.2 ने देखा, जो उस समय पी.डब्ल्यू.1 चेल्लादुराई पी.डब्ल्यू.3 के खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव करने के बाद लौट रहे थे, जो पी.डब्ल्यू.4 के लिए भोजन लेकर रसायल के खेत में आ रहे थे, उन्होंने भी इस घटना को देखा। नागप्पन पी.डब्ल्यू.5, जो बकाया मजदूरी के लिए रामकृष्णन पी.डब्ल्यू.2 से मिलने के लिए घटना स्थल की ओर जा रहा था, ने भी घटना को देखा। घटना के तुरंत बाद, पहला अपीलार्थी अपने साथ वीचारुवल ले गया और दूसरा अपीलार्थी मृतक रसायल के पैरों के पास कुदाल छोड़कर चला गया।

पी.डब्ल्यू.4 ने एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.7 उसी दिन दोपहर 3 बजे पुलिस उप-निरीक्षक, कामरची को दी। उप-निरीक्षक ने पी.डब्ल्यू.4 का कथन दर्ज किया, उसे पढ़ा और उसके हस्ताक्षर प्राप्त किए। आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने के बाद उसने अन्वेषण शुरू किया और घटना स्थल पर गया और पूछताछ की। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर का मानना था कि मृतक की मौत धड़ से सिर अलग होने से हुई है। अन्वेषण के दौरान, पुलिस ने 24-12-1973 को उप-मजिस्ट्रेट, चिदंबरम के समक्ष पी.डब्ल्यू1 से 5 तक के दं.प्र.सं. की धारा 164 के बयान दर्ज किये थे। समनुदेशन कार्यवाही के दौरान, पी.डब्ल्यू.4 पक्षद्रोही हो गया लेकिन पी.डब्ल्यू 1, 2 3 और 5 ने अभियोजन पक्ष का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिए। समनुदेशन के बाद, पी. डब्ल्यू. 1, 2, 3 और 5 ने समादेशिक न्यायालय के समक्ष दिए गए साक्ष्य को वापस ले लिया। अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित कराया गया और उनके साक्ष्य दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के तहत समादेशिक न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया। उच्च न्यायालय ने पीडब्ल्यू 1, 2, 3 और 5 के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के अन्तर्गत अंकित साक्ष्य, पर भरोसा किया। यह पाया गया कि

यह संतोषजनक ढंग से स्थापित किया गया था कि पहले अपीलार्थी ने मृतक की गर्दन के दाहिनी ओर काटा था, दूसरे अभियुक्त ने पहले अभियुक्त को यह कहते हुए उसे काटने के लिए उकसाया कि वह एक अनैतिक महिला है और पहले अपीलार्थी ने बाएं हाथ से उसके बाल पकड़े और वीचरूवल से उसकी गर्दन काट दी, सिर को धड़ से अलग कर दिया और अन्य अभियुक्त के साथ वहां से भाग गया। उच्च न्यायालय ने तीसरे अभियुक्त को इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया कि एफ.आई.आर. में यह उल्लेख नहीं था कि तीसरे अभियुक्त ने पहले अभियुक्त को मृतक की गर्दन काटने के लिए उकसाया था। उन्हें संदेह का लाभ दिया गया और दोषमुक्त कर दिया गया।

अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री मुल्ला ने प्रस्तुत किया कि धारा 288 के तहत सत्र न्यायालय में चिह्नित पीडब्लू 1,2,3 और 5 के वापस लिए गए साक्ष्य के आधार पर दोनों अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है। दूसरा, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गवाहों से दर्ज किए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की थी कि समादेशिक न्यायालय में दिए गए साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है। अंत में, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि किसी भी स्थिति में दूसरे अपीलार्थी का मामला तीसरे अभियुक्त के समान है और दूसरे अपीलार्थी को दोषमुक्त कर दिया जाना चाहिए था।

हमें गवाहों के प्रासंगिक साक्ष्य, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत उनके बयानों और उनके द्वारा समादेशिक न्यायालय में दिए गए साक्ष्य, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के तहत सत्र न्यायालय के रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया, के द्वारा लिया गया है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कानून के प्रश्नों पर विचार करने से पहले, हम पाते हैं कि दूसरे अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता की याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष के लिए मामला यह है कि दो अपीलार्थी

और तीसरा अभियुक्त घटना स्थल पर गए -पहला अपीलार्थी वीचारुवल से लैस था, दूसरा अपीलार्थी कुदाल से लैस था और तीसरा अभियुक्त निहत्था - रसायल पर अभिसारित हुए और पहले अभियुक्त ने एक कट दिया जिसके परिणामस्वरूप उसका सिर धड से अलग हो गया। हमें लगता है कि जब तीनों भाई रसायल को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ घटनास्थल पर गए, तो किसी भी उकसावे की संभावना नहीं थी। पहला अभियुक्त जिसने वास्तव में चोट पहुंचाई वह सबसे बड़ा भाई है। हमारे लिए यह प्रतिग्रहण करना करना मुश्किल है कि इससे पहले कि वह वास्तव में चोट पहुँचाता, उसे दूसरे अपीलार्थी की प्रेरणा की आवश्यकता थी। रामलिंगम पी.डब्ल्यू.1 के बयान में, जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के तहत प्रदर्श पी-2 के रूप में चिह्नित किया गया था, उसने कहा कि पहला अभियुक्त अरुवल, के साथ आया था, ए-2 एक कुदाल के साथ और ए-3 के साथ रसयाल अम्माल की ओर चला गया। वीचारुवल के साथ ए-1 ने रसायल अम्माल की दाहिनी गर्दन को काट दिया। अन्य लोग वहाँ खड़े थे। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा दूसरे अपीलार्थी को दी गई उकसाहट रामलिंगम के साक्ष्य में नहीं पाई जाती है। तथ्यों और मामले की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम महसूस करते हैं कि यह सबसे अधिक संभावना नहीं है कि दूसरे अपीलार्थी ने पहले अभियुक्त को उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप पहले अभियुक्त द्वारा घातक चोट कारित की गई। दूसरा अपीलार्थी संदेह के लाभ का हकदार है। उसकी अपील को स्वीकार किया जाता है और उसकी दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। उसे रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

अब हम विद्वान अधिवक्ता के पहले तर्क पर विचार करेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के तहत चिह्नित बयानों के आधार पर दोषसिद्धि विचार के लिए टिकाऊ नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 इस प्रकार हैः -

"अध्याय XVIII के तहत अभियुक्त की उपस्थिति में विधिवत अभिलिखित गवाह का साक्ष्य, पीठासीन न्यायाधीश के विवेकानुसार, यदि ऐसा गवाह पेश किया जाता है और उसकी जांच की जाती है, तो उसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अधीन सभी उद्देश्यों के लिए मामले में साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।"

विद्वान अधिवक्ता की दलील यह है कि धारा 288 के तहत चिह्नित साक्ष्य अस्वीकार्य है क्योंकि इसे केवल गवाहों को पूरा पढ़ा गया था और साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 में आवश्यक के रूप में उन्हें पारित नहीं किया गया था। सत्र न्यायालय में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, वह यह थी कि जब गवाहों ने अभियोजन पक्ष के प्रति प्रतिकूल बयान दिया, तो उनसे पूछा गया कि क्या उनसे समादेशिक न्यायालय में पूछताछ की गई थी। समादेशिक न्यायालय में उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य को लोक अभियोजक द्वारा गवाहों को पढ़ाया गया। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने साक्ष्य दिया था जैसा कि प्रदर्श में पाया गया था और उसने उस पर हस्ताक्षर किए थे। समादेशिक न्यायालय में दिए गए साक्ष्य को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के तहत सत्र न्यायालय के रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अपनाई गई प्रक्रिया को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि धारा 288 अनुध्यात करता है कि समादेशिक कार्यवाही के दौरान दिए गए साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अधीन मामले में साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, और इसलिए, प्रत्येक और प्रत्येक मार्ग जिस पर अभियोजन पक्ष निर्भर करता है, उसे गवाहों के सामने रखा जाना चाहिए था, इससे पहले कि अंशों को चिह्नित किया जा सके और मूल साक्ष्य के रूप में माना जा सके। साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 इस प्रकार हैः -

"किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में, जो उसने लिखित रूप में किये हैं या जो लेखबद्ध किये गए हैं और जो प्रश्नगत बैटन से सुसंगत हैं, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना, या ऐसे लेख साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी, किन्तु यदि उस लेख द्वारा उसका खंडन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किये जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन से किया जाना है।"

तारा सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1)] के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा व्यक्त किया गया था, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समादेशिक न्यायालय में साक्ष्य का उपयोग सत्र न्यायालय में तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि गवाह का सामना साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के तहत आवश्यक अपने पिछले साक्ष्य से नहीं किया जाता है। न्यायालय ने कहा कि यदि अभियोजन पक्ष पिछली गवाही को ठोस साक्ष्य के रूप में उपयोग करना चाहता है तो उसे गवाह का उन हिस्सों के साथ सामना करना चाहिए जिनका उपयोग उसका धारण करने के उद्देश्य से किया जाना था और तभी मामले को धारा 288 के तहत ठोस साक्ष्य के रूप में लाया जा सकता है। मामले के तथ्यों पर न्यायालय ने पाया कि जो कुछ हुआ वह यह था कि गवाहों से उनके पिछले बयानों के बारे में कुछ पूछा गया था और उन्होंने जवाब दिया कि वे जबरदस्ती के तहत किए गए थे। ऐसा प्रतीत नहीं होता कि गवाहों के पूरे पूर्व बयान उनके सामने रखे गए थे और उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने वास्तव में बयान दिए थे।

भगवान सिंह बनाम पंजाब राज्य [(1)] में, इस न्यायालय ने तारा सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपरोक्त) के मामले को विशिष्ट किया और कहा कि साक्ष्य अधिनियम की

धारा 145 का सहारा लेना केवल तभी आवश्यक है जब कोई गवाह इस बात से इनकार करता है कि उसने पूर्व बयान दिया था। जब गवाह पूर्व कथन को स्वीकार करता है, तो केवल पूर्व कथन को देखने की आवश्यकता होती है, जिस पर इस स्वीकारोक्ति के कारण आगे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि यह किया गया था। हिदायतुल्ला, मुख्य न्यायाधिपति ने, राजस्थान राज्य बनाम कर्तार सिंह, में समादेशिक न्यायालय में बयान को ठोस साक्ष्य के रूप में मानने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर विचार करते हुए कहा कि गवाहों का सामना समादेशिक न्यायालय में उनके बयानों से किया जाना चाहिए जिन्हें उन्हें विस्तार से पढ़ा जाना है। मुख्य न्यायाधिपति ने बताया कि मामले के गवाहों ने स्वीकार किया कि उनके बयान वास्तव में समादेशिक न्यायालय में दर्ज किए गए थे, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया कि वे सही बयान थे क्योंकि उन्हें पुलिस द्वारा इस तरह से गवाही देने के लिए कहा गया था। दोनों बयानों के बीच विसंगतियों को इंगित करना बेकार होता क्योंकि स्पष्टीकरण समान होता और परिस्थितियों में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया जाता।

इस प्रकार ऊपर निर्दिष्ट प्राधिकारों से यह स्पष्ट है कि धारा 288 की आवश्यकताओं का पूरी तरह से पालन किया जाएगा यदि गवाहों के बयानों को उनके सामने विस्तार से पढ़ा जाता है और वे स्वीकार करते हैं कि उन्होंने उन बयानों को समादेशिक न्यायालय में दिया है। इस मामले में आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया है और विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए हमले को विफल होना पड़ता है।

विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा कानूनी तर्क यह था कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गवाहों से दर्ज किए गए बयानों को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की थी कि उनके द्वारा समादेशिक न्यायालय में दिए गए साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है। उच्च

न्यायालय ने कहा कि "हम पी.डब्ल्यू.1 से 3 और 5 के 164 बयानों के संबंध में संतुष्ट हैं कि उन गवाहों द्वारा समादेशिक न्यायालय के समक्ष दिए गए बयान सही हैं और उन पर भरोसा किया जा सकता है" और यह अवलोकन करने के लिए आगे बढ़े कि "चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के तहत साक्ष्य में एक से अधिक बयान स्वीकार किए गए हैं, इसलिए समादेशिक न्यायालय के समक्ष एक गवाह के साक्ष्य की पुष्टि दूसरों द्वारा दिए गए बयान से होती है।" श्री मुल्ला, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज एक बयान से संकेत मिलता है कि पुलिस ने सोचा कि गवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके बदलने की संभावना थी और इसलिए, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत एक बयान हासिल करने का सहारा लिया। इस प्रकार अभिलिखित कथन का उपयोग समादेशिक न्यायालय में गवाह द्वारा दिए गए कथन की पुष्टि करने के लिए नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने राम चंद्र और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1)] में इस न्यायालय की कुछ टिप्पणियों पर भरोसा किया। उस मामले में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गवाह से दर्ज एक बयान में, मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित शब्दों में एक प्रमाण पत्र संलग्न किया:-

> "प्रमाणित किया कि बयान स्वेच्छा से दिया गया है। अभियुक्त को चेतावनी दी गई थी कि वह प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दे रहा है और उसका उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता है। मेरी उपस्थिति में दर्ज किया गया। यहाँ कोई पुलिस नहीं है। गवाह तब तक बाहर नहीं गया जब तक कि सभी गवाह बयान नहीं दे देते।"

न्यायालय ने पाया कि किया गया समर्थन उचित नहीं है, लेकिन समर्थन से यह निष्कर्ष निकालने से इनकार कर दिया कि उन गवाहों को कोई धमकी दी गई थी या यह आवश्यक रूप से अदालत में गवाह द्वारा दिए गए साक्ष्य को संदिग्ध या कम

विश्वसनीय बनाता है। सम्राट बनाम मनु चिक [2] मामले में पटना उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रानी महारानी बनाम जादूब दास [3] मामले में की गई टिप्पणियों में कहा गया है कि इस धारा के तहत प्राप्त गवाहों के बयान हमेशा संदेह पैदा करते हैं कि इसे स्वेच्छा से नहीं दिया गया था, पर विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया था। यह न्यायालय पटना मामले में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से सहमत नहीं था, लेकिन गोपीसेट्टी चिन्ना वेंकट सुब्बैया [1] में जे. सुब्बा राव, (जैसा कि वे तब थे) के दृष्टिकोण से सहमत था, जहां उन्होंने परमानंद बनाम सम्राट [2] में नागपुर उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को प्राथमिकता दी, यह देखा गया कि केवल यह तथ्य कि गवाह का बयान पहले धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था, इसे खारिज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह देखा गया कि न्यायालय को इसे सावधानी के साथ स्वीकार करना चाहिए और यदि अभिलेख पर ऐसी अन्य परिस्थितियाँ हैं जो ऐसे गवाहों के साक्ष्य की सच्चाई का समर्थन करती हैं, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जाँच के दौरान पुलिस अधिकारी, कभी-कभी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत गवाह का बयान दर्ज करना समीचीन समझता है। ऐसा तब होता है जब किसी अपराध के गवाह अभियुक्त के साथ निकटता से जुड़े होते हैं या जहाँ अभियुक्त बहुत प्रभावशाली होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। दर्ज किए गए 164 बयान में मजिस्ट्रेट का समर्थन है कि बयान गवाह द्वारा दिया गया था। मात्र तथ्य यह है कि पुलिस के पास संदेह करने के कारण थे कि गवाह को पकड़ लिया जा सकता है और मजिस्ट्रेट द्वारा उनके बयान दर्ज करना उचित था, इस प्रकार दर्ज किए गए गवाहों के बयान दागी नहीं होंगे। यदि गवाह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट को दिए गए बयान पर कायम रहता है, तो कोई समस्या पैदा नहीं होती है। यदि गवाह समादेशिक न्यायालय में धारा 164 के तहत अपने द्वारा दिए गए बयान से मुकर जाता है, तो गवाह से उसके पहले के बयान पर प्रतिप्रिक्षा की जा सकती है। लेकिन अगर वह जांच से पहले धारा 164 के

तहत दिए गए अपने बयान पर कायम रहता है और सत्र न्यायालय में उससे जवाब देता है, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। यह न्यायालय के लिए है कि वह सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करे, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि गवाह ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में देरी की थी कि गवाह पर विश्वास किया जाना चाहिए या नहीं। यह तथ्य कि पुलिस के पास मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज धारा 164 का बयान था, अपने आप में उसके साक्ष्य को दूषित नहीं करेगा।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 यह स्पष्ट करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए बयान पर समादेशिक न्यायालय में गवाहों द्वारा दिए गए बयानों की पुष्टि के लिए भरोसा किया जा सकता है। इस न्यायालय ने अपना विचार व्यक्त किया है कि यद्यपि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान साक्ष्य नहीं हैं, लेकिन यह समादेशिक न्यायालय में पहले [1971] 1 एस.सी.आर. 56 के माध्यम से जो कहा गया है, उसकी पुष्टि करता है। उच्च न्यायालय धारा 164 के तहत गवाहों के बयान पर भरोसा करने में सही था क्योंकि यह समादेशिक न्यायालय के समक्ष उनके बाद के साक्ष्य की पुष्टि करता है। विद्वान अधिवक्ता की याचिका समान रूप से अस्थिर है कि एक गवाह का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 288 के तहत दर्ज बयान धारा 288 के तहत दूसरे गवाह के बयान की पुष्टि नहीं कर सकता है। बयानों को कानून में ठोस साक्ष्य के रूप में माना जाता है और हम एक गवाह के बयान को दूसरे की पुष्टि करने वाला मानने में कोई त्रुटि नहीं देखते हैं। विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए कानून के सवाल का परिणाम विफल हो जाता है। प्रथम अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी जाती है और उसकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जाती है। दूसरे अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाता है और उसकी दोषसिद्धि और सजा को अपास्त किया जाता है। उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

वी.डी.के.

प्रथम अपीलार्थी की अपील खारिज की गई।

द्वितीय अपीलार्थी की अपील स्वीकार की गई।

(1) [1951] एस.सी.आर. 729 पेज 6

(1) [1952] एस.सी.आर. 812 पेज 7

(2) [1971] 1 एस.सी.आर. 56 पेज 7

(1) (1968) 3 एस.सी.आर. 354 पेज 8

(2) ए.आई.आर. 1938 पटना 290-295 पेज 8

(3) 27 केल. 295 पेज 8

(1) आई.एल.आर. (1955) ए.पी. 633-38 पेज 9

(2) ए.आई.आर. 1940 नाग.34 पेज 9

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

*****